



केन्द्रीय

सम्माननीय जीवन
समान अधिकार

मानवाधिकार

दैनिक

| नागपुर. मंगलवार, 12 अगस्त 2025

| वर्ष - 13

| अंक - 166

| पृष्ठ - 4

| मुल्य - 2 रु.

संपादक : मिलिंद दहिवले

न्यूज गैलरी

किसानों के कल्याण और एपीएमसी के आधुनिकीकरण के लिए उच्च स्तरीय बैठक आवश्यक

नई दिल्ली – महाराष्ट्र के विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने कृषि उत्पादन प्रबंधन, किसानों को उचित पारिश्रमिक, भंडारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय और राज्य मंत्रियों की तत्काल उच्च स्तरीय बैठक की मांग की है। साथ ही, किसानों के आर्थिक कल्याण और कृषि दक्षता बढ़ाने के लिए ठोस उपाय सुझाते हुए मंत्री श्री रावल ने शुक्रवार को दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री से एक केंद्रीय योजना तैयार करने का अनुरोध भी किया। मंत्री जयकुमार रावल ने बताया कि महाराष्ट्र सहित पूरे देश में प्याज, दालें, संतरे, अनार, केले और फूलों जैसे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालाँकि, अपर्याप्त बाजार व्यवस्था और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण, किसानों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है। कटाई के बाद अपर्याप्त उपकरणों के कारण कुछ नुकसान भी होता है। इससे किसानों की आय और देश की कृषि दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रावल ने कृषि उपज के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विशेष सहायता योजनाएँ, विकेन्द्रीकृत वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएँ, कोल्ड चेन, डिजिटल इन्वेंट्री प्रबंधन और कुशल लॉजिस्टिक्स प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बाजार सूचना प्रणालियों के एकीकरण के माध्यम से उत्पादन और मूल्य प्रवृत्तियों का सटीक पूर्वानुमान लगाकर किसानों को समय पर जानकारी प्रदान करने पर भी जोर दिया। इससे नीति निर्माताओं को सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। रावल ने कृषि उपज मंडी समितियों के आधुनिकीकरण के लिए एक केंद्रीय योजना तैयार करने की मांग की, जिसमें ढके हुए नीलामी मंच, ग्रेडिंग-तौल प्रणाली, कोल्ड स्टोरेज, शुष्क गोदाम, पैकेजिंग केंद्र और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएँ शामिल हों। उन्होंने एपीएमसी परिसरों में अप्रयुक्त स्थान पर छोटी कृषि-प्रसंस्करण इकाइयाँ और किसान-केंद्रित सुविधाएँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन और तकनीकी सहायता का भी अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि एपीएमसी को ई-नाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए सक्सेसि और क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए। रावल ने कहा कि इस बैठक से एक ठोस रोडमैप तैयार करके किसानों के हितों की रक्षा की जा सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे उपाय कृषि व्यवसाय को टिकाऊ बनाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार में भारत की अग्रणी भूमिका को मजबूत करेंगे।

नारली पूर्णिमा और ज्येष्ठ गौरी विसर्जन के दिन स्थानीय अवकाश

मुंबई – वर्ष 2025 में गोपालकाला (दहीहांडी) और अनंत चतुर्दशी के स्थान पर नारली पूर्णिमा और ज्येष्ठ गौरी विसर्जन के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। ये स्थानीय अवकाश मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिलों में राज्य सरकार और अर्ध-सरकारी कार्यालयों पर लागू हैं और इस संबंध में एक सरकारी शुद्धिपत्र जारी किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2025 में महत्वपूर्ण त्योहारों और समारोहों के लिए स्थानीय छुट्टियों की आधिकारिक घोषणा की है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के 18 दिसंबर 2025 के सरकारी परिपत्र के अनुसार, शनिवार, 16 अगस्त 2025 को गोपालकाला (दहीहांडी) और शनिवार, 6 सितंबर 2025 को अनंत चतुर्दशी की छुट्टियाँ घोषित की गई थीं। हालाँकि, सामान्य प्रशासन विभाग के 7 अगस्त 2025 के सरकारी शुद्धिपत्र के अनुसार, 18 दिसंबर 2025 को घोषित छुट्टियों के बजाय, 8 अगस्त 2025 को नारली पूर्णिमा और 2 सितंबर 2025 को ज्येष्ठ गौरी विसर्जन के अवसर पर स्थानीय छुट्टियाँ घोषित की गई हैं। सरकारी शुद्धिपत्र में उल्लेख किया गया है कि ये आदेश मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिलों के सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों पर लागू रहेंगे।

चट्टान गिरने से कार 500 मीटर गहरी खाई में गिरी, एक ही परिवार के 6 की मौत

हिमाचल – चंबा जिला के चुराह उपमंडल में बड़ी चट्टान पहाड़ी से स्विफ्ट गाड़ी पर गिर गई। इससे कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई और छह लोगों की जान चली गई। जिले के चुराह में एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार छह लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो महिला, दो पुरुष और दो बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कार जहां गिरी वह खाई 500 मीटर

गहरी थी। जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात लगभग 9:20 पर एक स्विफ्ट गाड़ी नंबर HP 44 4246 जो कि भजराड़ से श्रीगर गांव जा रही थी। साउया पथरी पर चलती गाड़ी में पहाड़ से बहुत बड़ी चट्टान गिरने से एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी में पहाड़ से बहुत बड़ी चट्टान गिर गई। इससे कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर नीचे खाई में गिर गई। कार में सवार सभी छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 7 अगस्त की रात लगभग 9:20 पर एक

स्विफ्ट गाड़ी नंबर HP 44 4246 जो की भजराड़ से श्रीगर गांव जा रही थी। साउया पथरी पर चलती गाड़ी में पहाड़ से बहुत बड़ी चट्टान गिरने से एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी 500 मीटर नीचे खाई में गिर गई। गाड़ी में छह व्यक्ति सवार थे, सभी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। कार में सवार सभी छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 7 अगस्त की रात लगभग 9:20 पर एक

आधार के ज़रिए पहचान साबित करने की प्रक्रिया ने नया मुकाम

नई दिल्ली – भुवनेश कुमार, सौईओ ने कहा कि यूआईडीएआई, गांवों से लेकर बड़े शहरों तक, आधार के ज़रिए पहचान साबित करने की प्रक्रिया को कामयाब बनाने के लिए सरकारों, बैंकों और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, आज़ादी महज एक कदम की दूरी पर है। आधार के ज़रिए पहचान साबित करने की प्रक्रिया के ज़रिए आधार धारक अपनी पहचान तुरंत, सुरक्षित और संपर्क रहित तरीके से, कभी भी, कहीं भी सत्यापित कर सकते हैं, और खास बात ये है कि इसके लिए उन्हें किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत भी नहीं है। 10 अगस्त 2025 को, यूआईडीएआई ने पहचान साबित करने की प्रक्रिया के 200 करोड़ आदान- प्रदान होने का जश्न मनाया, जो भारत की सरल, सुरक्षित और कागज रहित, पहचान पुख्ता करने की व्यवस्था की ओर तेज़ी से बढ़ती प्रगति को दर्शाता है। इस व्यवस्था को अपनाने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। 2024 के मध्य तक 50 करोड़ आदान-प्रदान दर्ज किए गए। जनवरी 2025 में यह संख्या करीब पाँच महीनों में दोगुना होकर 100 करोड़ हो गई। इसके बाद छह महीने से भी कम वक्त में, यह आँकड़ा फिर से दोगुना होकर 200 करोड़ के अप्रत्याशित कामयाबी के मुकाम तक पहुँच गया है। इस उपलब्धि के मौके पर यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सौईओ) भुवनेश कुमार ने कहा, "इतने कम समय में 200 करोड़, आधार पहचान साबित करने की प्रक्रिया के आदान प्रदान के मुकाम तक पहुँचना, निवासियों और सेवा प्रदाताओं, दोनों के आधार के सुरक्षित, समावेशी और नए बदलावों से बनी व्यवस्था में विश्वास को दर्शाता है। छह महीने से भी कम वक्त में 100 करोड़ से 200 करोड़ आदान प्रदान तक का सफ़र, इसके विस्तार और देश की पुख्ता डिजिटल तैयारी का सुबूत है। गाँवों से लेकर बड़े शहरों तक, यूआईडीएआई सरकारों, बैंकों और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर, आधार के ज़रिए पहचान साबित करने की व्यवस्था को एक बड़ी कामयाबी बनाने और हर भारतीय को अपनी पहचान तुरंत, सुरक्षित तरीके से और कहीं भी साबित करने की ताकत प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।"

वाली सबसे तेज़ ट्रेन है।

नागपुर और पुणे दोनों ही तेज़ी से विकसित हो रहे बड़े शहर हैं जहाँ कई छोटे और मध्यम उद्योग, शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थान, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल आदि हैं। अजनी (नागपुर) और पुणे के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू होने से इन दोनों शहरों और रास्ते में पड़ने वाले कस्बों के बीच काम, व्यवसाय, पढ़ाई और पर्यटन के लिए यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों की एक बड़ी आबादी को बहुत लाभ होगा। यह नियमित यात्रा और विशेष पर्यटन पर जाने वाले व्यापारियों, छात्रों, कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगा और व्यापार एवं वाणिज्य के अवसरों को बढ़ाने के अलावा पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।

विशेषताएँ: यात्री सुविधाएँ •एसी: - सभी कोच एयर कंडीशनिंग सिस्टम से सुसज्जित हैं •स्वचालित तापमान नियंत्रण: - यात्रियों की संख्या के आधार पर तापमान स्वचालित रूप से समायोजित होता है •सीटें: - लंबी दूरी की यात्रा के लिए आरामदायक

डिजाइन वाली सीटें •प्रकाश व्यवस्था: - सभी कोच में एलईडी और परिवेश प्रकाश व्यवस्था •दरवाजे: - सभी कोच में स्वचालित स्टाइडिंग दरवाजे •खिड़कियाँ: - मनोरम दृश्यों के लिए और पर्यटन स्थल आदि हैं। अजनी (नागपुर) और पुणे के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू होने से इन दोनों शहरों और रास्ते में पड़ने वाले कस्बों के बीच काम, व्यवसाय, पढ़ाई और पर्यटन के लिए यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों की एक बड़ी आबादी को बहुत लाभ होगा। यह नियमित यात्रा और विशेष पर्यटन पर जाने वाले व्यापारियों, छात्रों, कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगा और व्यापार एवं वाणिज्य के अवसरों को बढ़ाने के अलावा पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।

सुरक्षा विशेषताएँ • अग्नि सुरक्षा: आग का पता लगाने और बुझाने की प्रणालियाँ • सीसीटीवी निगरानी: पूरी ट्रेन में कैमरों से निगरानी • आपातकालीन संचार: प्रत्येक कोच में इंटरकॉम सिस्टम • ब्रेकिंग सिस्टम: पुनर्योजी ब्रेकिंग जो 30% तक ऊर्जा बचाती है • दोहरी सस्पेंशन प्रणाली: तेज़ गति भी आराम सुनिश्चित करती है

'मेक इन इंडिया' पहल के एक उत्पाद के रूप में, यह ट्रेन अत्याधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इन ट्रेनों के शुभारंभ से नवाचार और कनेक्टिविटी के केंद्र के रूप में महाराष्ट्र की स्थिति मजबूत होगी और क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

...अंदर के पेज पर

आईटीआई में तकनीकी शिक्षा और 20 व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम 15 सितंबर से शुरू होंगे – लोढ़ा

मुंबई – महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार नीति 2025: "मुख्यमंत्री उद्यमिता और नवाचार महाफंड" योजना लागू की जाएगी। सरकार के पास विभिन्न तकनीकी शिक्षा प्राप्त 30 लाख युवाओं का रिकॉर्ड है। इन सभी को ईमेल भेजकर एआई के माध्यम से परखा जाएगा। इसमें से विभिन्न तरीकों से पांच लाख युवाओं का चयन किया जाएगा। फिर से स्क्रीनले के बाद, मूल्यांकन परीक्षण, प्रतियोगिताओं और हैकathon के माध्यम से 1 लाख उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अंतिम चरण में 25,000 चयनित उम्मीदवारों को तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करके सफल उद्यमी और स्टार्टअप तैयार करना उद्देश्य है। कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने बताया कि 15 सितंबर से आईटीआई में तकनीकी शिक्षा के साथ व्यक्तित्व विकास के 20 पाठ्यक्रम शुरू होंगे। लोढ़ा मंत्रालय में कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता नवाचार विकास विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इस अवसर पर कौशल विकास आयुक्त लहराज माली भी उपस्थित थे।

लोढ़ा ने कहा कि "महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार नीति 2025" को मंजूरी दे दी गई है और इस नीति को आधिकारिक तौर पर लागू किया जाएगा। यह नीति महाराष्ट्र राज्य नवाचार सोसायटी के माध्यम से लागू की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य महाराष्ट्र में भारत का सबसे गतिशील और दूरदर्शी स्टार्टअप हब बनाना है। इस नीति में अगले पाँच वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण है और इसका लक्ष्य 1.25 लाख उद्यमी बनाना और 50,000 स्टार्टअप को मंजूरी देना है। शहरी, ग्रामीण, महिला और युवा उद्यमियों सहित सभी क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियों और वंचित समुदायों

पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस नीति का एक महत्वपूर्ण घटक यह है कि चयनित उम्मीदवारों को वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी में 5.00 लाख रुपये से 10.00 लाख रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। पाँच साल की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये का कोष जुटाया जाएगा। राज्य का प्रत्येक विभाग अपने वार्षिक आवंटन का 0.5% उद्यमिता और उद्यमिता के लिए उपलब्ध कराएगा। ये सभी योजनाएँ महाराष्ट्र राज्य नवाचार सोसाइटी की सहायता से क्रियान्वित होगी, जो राज्य में नवाचार और उद्यमिता के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करेगी।

पुण्यश्लोक खाशाबा जाधव अहिल्यादेवी होल्कर स्मृति दिवस के अवसर पर मुंबई में पारंपरिक खेल महाकुंभ का आयोजन – लोढ़ा ने कहा कि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर के स्मृति दिवस के अवसर पर मुंबई में 'ओलंपिक वीर खशाबा जाधव पारंपरिक खेल महाकुंभ' का आयोजन किया गया है। 13 से 22 अगस्त तक, कुर्ला स्थित जामसाहेब मुकुंदम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मैदान में मुंबईवासियों को पारंपरिक खेलों का रोमांच देखने को मिलेगा। इस खेल महाकुंभ के माध्यम से लेज़िम, फुगड़ी और लागोरी, विटी दांडू सहित शिवकालीन पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित किया जाएगा। पारंपरिक खेलों के इस खेल महोत्सव में कबड्डी, खो-खो, लागोरी, लेझिम, रस्साकशी, मल्लखंब, पावनखिंड दौड़, कुश्ती, प्यादा फाड़टिंग, विटी-दंडू, रस्सी कूद, फुगड़ी और योगा खेल श्रेणियों में महिलाओं और पुरुषों के लिए मैचों का आयोजन किया गया है। मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने जनता से कुर्ला के जामसाहेब मुकुंदम सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के मैदान में होने वाले इस खेल महोत्सव में भाग लेने की अपील भी की है।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए 368 करोड़ 86 लाख 85 हजार रुपये

मुंबई – राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है। राज्य सरकार ने जून 2025 में छत्रपति संभाजीनगर, अमरावती संभाग में और सितंबर 2024 से अक्टूबर 2024 तक धाराशिव, छत्रपति संभाजीनगर और धुले जिलों में हुई कृषि फसलों को हुए नुकसान के लिए 368 करोड़ 86 लाख 85 हजार रुपये की राहत निधि को मंजूरी दी है, ऐसा राहत एवं पुनर्वास मंत्री

मकरंद जाधव-पाटिल ने बताया। इस संबंध में सरकारी निर्णय जारी कर दिए गए हैं। भारी बारिश और बाढ़ के कारण फसल क्षति के लिए स्वीकृत निधि में छत्रपति संभाजीनगर प्रभाग के लिए 14 करोड़ 54 लाख 64 हजार रुपये, अमरावती प्रभाग के लिए 86 करोड़ 23 लाख 38 हजार रुपये और धाराशिव, छत्रपति संभाजीनगर और धुले जिलों में सितंबर 2024 से अक्टूबर 2024 तक फसल क्षति के लिए 268 करोड़ 8 लाख 83 हजार

रुपये शामिल हैं। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल ने कहा कि सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के प्रति संवेदनशील है और उन्होंने जिला कलेक्टरों को प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल प्रभावित फसलों का पंचनामा करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने भी भारी बारिश और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों की फसलों का तत्काल पंचनामा किया और प्रभावित किसानों को दी जाने

वाली धनराशि को मंजूरी दी।

जून 2025 में, छत्रपति संभाजीनगर विभाग के छत्रपति संभाजीनगर जिले में 171 किसानों के 72.32 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के लिए 16.01 लाख रुपये, हिंगोली जिले में 3 हजार 247 किसानों के 1611.37 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के लिए 360.45 लाख रुपये, नांदेड़ जिले में 7 हजार 498 किसानों के 4790.78 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के लिए 1076.19 लाख रुपये और बीड जिले में 103 किसानों के 11

हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के लिए 1.99 लाख रुपये शामिल हैं।

अमरावती संभाग में, अमरावती जिले में 2,240 किसानों के 1312.02 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के लिए 275.79 लाख रुपये, अकोला जिले में 6,136 किसानों के 3790.31 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के लिए 405.90 लाख रुपये, यवतमाल जिले में 186 किसानों के 130.50 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के लिए 25.45 लाख रुपये, बुलढाणा जिले में 90,383 किसानों के 11

87390.02 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के लिए 7445.03 लाख रुपये और वाशिम जिले में 8,527 किसानों के 5162.28 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के लिए 471.21 लाख रुपये शामिल हैं।

सितंबर 2024 से अक्टूबर 2024 तक, निधि में धाराशिव जिले में 3 लाख 27 हजार 939 किसानों के 189610.70 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के लिए 26143.38 लाख रुपये, छत्रपति संभाजीनगर जिले में 7 हजार 548 किसानों के

4891.05 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के लिए 665.41 लाख रुपये और धुले जिले में एक किसान के 0.3 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के लिए 0.04 लाख रुपये शामिल हैं।

राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री जाधव-पाटिल ने भी कहा कि इस निर्णय से प्रभावित किसानों को राहत मिलेगी और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों ने संतोष व्यक्त किया है क्योंकि सरकार ने त्वरित आकलन करके वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।

संपादक की कलम से धराली में कितनी बर्बादी...

तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। सेना के चिन्कू और MI-17 हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने के बाद हालात कैसे हैं? इसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से तबाही के निशान देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही का मंजर कितना भयंकर है? चारों तरफ मलबा ही मलबा है। पूरा इलाका पानी और मलबे से भरा दिखाई दे रहा है। NDRF और SDRF के जवान अभी भी यहां जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। इसरो/एनआरएससी ने दो तस्वीरें जारी की हैं। पहली सैटेलाइट तस्वीर 16 जून 2024 की है, दूसरी सैटेलाइट तस्वीर हादसे के बाद 7 अगस्त 2025 की है। उत्तराखंड के धराली और हरसिल में 5 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ का आकलन करने के लिए कार्टोसैट-2एस डेटा का उपयोग किया है।



मिलिंद दहीवले
संपादक

महाराष्ट्र सरकार 20, 21, 29 और 30 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले 1,000 करोड़ रुपये मूल्य के बांड बेच रही है

मुंबई - महाराष्ट्र सरकार के 20 वर्षीय 1000 करोड़ रुपये के '7.14% महाराष्ट्र सरकारी बॉन्ड, 2045' (9 जुलाई 2025 को जारी) की बिक्री सरकार की संशोधित अधिसूचना में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इस ऋण से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार के विकास कार्यों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा, वित्त विभाग की सचिव शैला ए. ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया।

गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी पद्धति (संशोधित) के अनुसार, सरकारी ऋण प्रतिभूतियों की कुल अधिसूचित राशि का 10 प्रतिशत पात्र व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों को आवंटित किया जाएगा। हालाँकि, किसी निवेशक को कुल अधिसूचित राशि का अधिकतम 1 प्रतिशत ही आवंटित किया जाएगा।

यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 12 अगस्त, 2025 को मुंबई स्थित अपने कार्यालय में आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए बोलियां 12 अगस्त, 2025 को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली, भारतीय रिजर्व बैंक, कोर बैंकिंग समाधान, (ई-कुबेर) प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत की जानी हैं।

प्रतिस्पर्धी बोलियाँ ई-कुबेर प्रणाली के अनुसार कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से सुबह 10:30 बजे से

11:30 बजे तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियाँ ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। नीलामी के परिणाम उसी दिन भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। सफल बोलीदाताओं द्वारा राशि का भुगतान 13 अगस्त, 2025 को नकद, बैंकर्स चेक/ पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में उनके खाते पर आहरित चेक के माध्यम से बैंक कार्य समय समाप्त होने से पहले अग्रिम भुगतान द्वारा किया जाएगा।

बॉन्ड की अवधि 20 वर्ष है और यह 9 जुलाई, 2025 से शुरू होगा और 9 जुलाई, 2045 को इसका पूरा भुगतान किया जाएगा। ब्याज दर 7.14 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। बॉन्ड की मूल कीमत पर मूल तिथि से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी और 9 जुलाई को अर्ध-वार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश को वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के प्रयोजन के लिए पात्र माना जाएगा। ये प्रतिभूतियाँ पुनर्विक्रय और खरीद के लिए स्वीकार्य होंगी, वित्त विभाग ने सूचित किया है।

महाराष्ट्र सरकार के 21 वर्षीय 1000 करोड़ रुपये के '7.14% महाराष्ट्र सरकारी बॉन्ड, 2046' (9 जुलाई 2025 को जारी) की बिक्री सरकार की संशोधित अधिसूचना में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इस ऋण से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार के विकास कार्यों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा, यह जानकारी वित्त विभाग की सचिव शैला ए. ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी।

गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी पद्धति (संशोधित) के अनुसार, सरकारी ऋण प्रतिभूतियों की कुल अधिसूचित राशि का 10 प्रतिशत पात्र व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों को आवंटित किया जाएगा। हालाँकि, किसी निवेशक को कुल अधिसूचित राशि का अधिकतम 1 प्रतिशत ही आवंटित किया जाएगा।

यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 12 अगस्त, 2025 को मुंबई स्थित अपने कार्यालय में आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए बोलियां 12 अगस्त, 2025 को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली, भारतीय रिजर्व बैंक, कोर बैंकिंग समाधान, (ई-कुबेर) प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत की जानी हैं।

प्रतिस्पर्धी बोलियाँ ई-कुबेर प्रणाली के अनुसार कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से सुबह 10:30 बजे से

11:30 बजे तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियाँ ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। नीलामी के परिणाम उसी दिन भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। सफल बोलीदाताओं द्वारा राशि का भुगतान 13 अगस्त, 2025 को नकद, बैंकर्स चेक/ पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में उनके खाते पर आहरित चेक के माध्यम से बैंक कार्य समय समाप्त होने से पहले अग्रिम भुगतान द्वारा किया जाएगा।

बॉन्ड की अवधि 21 वर्ष है और यह 9 जुलाई, 2025 से शुरू होगा और 9 जुलाई, 2046 को पूरी तरह से चुकाया जाएगा। ब्याज दर 7.14 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। बॉन्ड की मूल कीमत पर मूल तिथि से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी और 9 जुलाई को अर्ध-वार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश को वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के प्रयोजन के लिए पात्र माना जाएगा। ये प्रतिभूतियाँ पुनर्विक्रय और खरीद के लिए स्वीकार्य होंगी, वित्त विभाग ने सूचित किया है।

महाराष्ट्र सरकार के 29 वर्ष की

परिपक्वता वाले '7.17 प्रतिशत ब्याज वाले महाराष्ट्र सरकार बांड, 2054' (6 अगस्त 2025 को जारी) के '1000 करोड़ रुपये की बिक्री सरकार की संशोधित अधिसूचना में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। वित्त विभाग की सचिव शैला ए. ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस ऋण से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार के विकास कार्यों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी पद्धति (संशोधित) के अनुसार, सरकारी ऋण प्रतिभूतियों की कुल अधिसूचित राशि का 10 प्रतिशत पात्र व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों को आवंटित किया जाएगा। हालाँकि, किसी निवेशक को कुल अधिसूचित राशि का अधिकतम 1 प्रतिशत ही आवंटित किया जाएगा।

यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 12 अगस्त, 2025 को मुंबई स्थित अपने कार्यालय में आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए बोलियां 12 अगस्त, 2025 को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली, भारतीय रिजर्व बैंक, कोर बैंकिंग समाधान, (ई-कुबेर) प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत की जानी हैं। प्रतिस्पर्धी बोलियाँ ई-कुबेर प्रणाली के अनुसार कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।

फसलों को कीड़ों और कीटों से बचाना भरपूर फसल की गारंटी है

राज्य और नागपुर संभाग में संतोषजनक बारिश हुई है और बुवाई भी पूरी हो चुकी है। फसलें खेतों में खड़ी हैं और किसानों को उनकी वृद्धि और स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना होगा। अगस्त महीने में फसलों की वृद्धि के साथ-साथ, किसानों को कीटों और इल्लियों के प्रकोप को रोकने की भी योजना बनानी होगी। यह विशेष लेख कपास की फसलों पर फूल छेदक और गुलाबी सुंडी के खतरे के साथ-साथ सोयाबीन, तुअर और कपास की फसलों पर दिखाई देने वाले हमानी इल्लियों के खतरे से बचाव के लिए कृषि विभाग द्वारा दी गई सलाह पर आधारित है।

जुलाई के दूसरे सप्ताह से कपास की फसलों पर दिखाई देने वाले फूल छेदक कीटों और उसी महीने के अंतिम सप्ताह व अगस्त के प्रथम सप्ताह से गुलाबी सुंडी के प्रकोप से फसल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, कृषि विभाग ने किसानों को एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत रसचूसक कीटों और गुलाबी सुंडी के प्रबंधन पर मार्गदर्शन दिया है। साथ ही, कृषि विभाग ने सोयाबीन, कपास और अरहर की फसलों को बहुभक्षी सुंडी (होलोट्रीचिया प्रजाति)

से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कीट प्रबंधन की सलाह दी है। कपास की फसल की शुरुआती अवस्था में, कपास की फसल पर लगने वाले मुख्य कीट एफिड्स, लीफहॉप्स और फ्लावर बग्ग हैं। सूखी कपास की फसल में, एफिड्स की उपस्थिति जुलाई के दूसरे सप्ताह से, लीफहॉप्स की उपस्थिति जुलाई के अंतिम सप्ताह से और फ्लावर बग्ग की उपस्थिति अगस्त के पहले सप्ताह से देखी जाती है। गुलाबी बॉलवर्म का संक्रमण अगस्त के महीने में प्युपा के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा, ब्लूमैनी वर्म (होलोट्रीचिया प्रजाति) एक बहुभक्षी कीट है और महाराष्ट्र में, होलोट्रीचिया सेरेटा प्रजाति मुख्य रूप से सोयाबीन, कपास और अरहर की फसलों को नुकसान पहुँचाती है। किसानों को इन सभी प्रकार के कीटों के प्रबंधन के लिए उपाय करने की आवश्यकता है।

एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत, बीटी कपास पर कीटनाशकों का छिड़काव नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से कपास चूसने वाले कीटों के प्रबंधन के लिए। समय-समय पर प्रभावित शाखाओं, पत्तियों और अन्य पत्तियों को इकट्ठा करें और उन्हें कीटों के साथ नष्ट करें। कपास कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं को पोषित करने के लिए, लोबिया के साथ अंतर-फसल करें। समय पर अंतर-फसल लगाकर फसल को खपतवार मुक्त रखें। उर्वरक की मात्रा मृदा परीक्षण के आधार पर अपनाई जानी चाहिए और नाइट्रोजन उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए। इसके अलावा, यदि एफिड्स, लीफहॉप्स और थ्रिप्स की संयुक्त औसत संख्या अधिक पाई जाती है, तो नियंत्रण के लिए रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए, बुप्रोफेजिन 25 प्रतिशत प्रवाह दर 20 मिली। या फिप्रोनिल 5 प्रतिशत प्रवाह दर 30 मिली। या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत 2.5 मिली। इनमें से किसी भी एक कीटनाशक को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।

कपास की फसल में गुलाबी सुंडी के प्रबंधन के लिए, अंकुरण के 40 से 45 दिन बाद फेरोमोन (सुगंध) जाल का उपयोग करना चाहिए। प्रति एकड़ दो फेरोमोन (सुगंध) जाल या प्रति हेक्टेयर पाँच फेरोमोन (सुगंध) जाल लगाने चाहिए। यदि इन जालों में



लगातार तीन दिनों तक आठ से दस पतंगे दिखाई दें, तो गुलाबी सुंडी के प्रबंधन के उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही, बड़े पैमाने पर जाल लगाने के लिए प्रति हेक्टेयर 15 से 20 सुगंधित जाल लगाने चाहिए। फसल में लार्वा की नियमित रूप से खोज की जानी चाहिए और उन लार्वा को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। फसल के अंकुरण के 35 से 40 दिन बाद हर 15 दिन में 5 प्रतिशत नीम अर्क या एजडिरेक्टिन 300 पीपीएम 50 मिली प्रति 10 लीटर पानी का छिड़काव करें। यदि गुलाबी सुंडी का प्रकोप 5 प्रतिशत से

अधिक पाया जाता है, तो निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसी एक का छिड़काव करें: क्विनोफोस 25 प्रतिशत मिलीलीटर या क्लोरोपाइरीफोस 20 प्रतिशत तरल 25 मिलीलीटर या प्रोफेफोस 50 प्रतिशत 30 मिलीलीटर या इंडोक्साकाब 15.8 प्रतिशत 10 मिलीलीटर या डेल्टामेथ्रिन 2.8 प्रतिशत 10 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

सोयाबीन, कपास और अरहर की फसलों को बहुभक्षी मिलीबग (होलोट्रीचिया प्रजाति) से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए, कीटनाशक

का पहला छिड़काव बबूल, नीम और बोरेक्स जैसे पेड़ों पर उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जहाँ यह कीट लगातार मौजूद रहता है। कीटनाशकों का प्रयोग करते समय श्रमिकों को सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो पहले छिड़काव के 3 सप्ताह बाद दूसरा छिड़काव किया जाना चाहिए।

हमानी इल्ली बारिश के बाद मिट्टी में अंडे देती है। यह इल्ली ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, गेहूँ, गन्ना, मिर्च, मूंग, कुसुम, बैंगन, कपास और सूरजमुखी जैसी फसलों की जड़ों को नष्ट कर देती है। इससे फसलें उखड़कर कीटनाशकों में से किसी एक का छिड़काव करें: क्विनोफोस 25 प्रतिशत मिलीलीटर या क्लोरोपाइरीफोस 20 प्रतिशत तरल 25 मिलीलीटर या प्रोफेफोस 50 प्रतिशत 30 मिलीलीटर या इंडोक्साकाब 15.8 प्रतिशत 10 मिलीलीटर या डेल्टामेथ्रिन 2.8 प्रतिशत 10 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

सोयाबीन, कपास और अरहर की फसलों को बहुभक्षी मिलीबग (होलोट्रीचिया प्रजाति) से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए, कीटनाशक

40 प्रतिशत इमिडाक्लोप्रिड 40 प्रतिशत दानेदार 5 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी को तने के पास डालना चाहिए या कार्बोप्थ्यूरीन 3 प्रतिशत दानेदार 33.30 किलोग्राम या थायोमेथोक्सम 0.4 प्रतिशत बिफेन्थ्रिन 0.8 प्रतिशत दानेदार 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या थायोमेथोक्सम 0.9 प्रतिशत फिप्रोनिन 2 प्रतिशत दानेदार 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को तने के पास मिट्टी में तब मिलाना चाहिए जब मिट्टी नम हो।

कृषि विभाग सदैव किसानों के साथ मजबूती से खड़ा है। वैज्ञानिक जानकारी के माध्यम से किसानों को सही समय पर सही सलाह देकर फसल को नुकसान से बचाने और भरपूर फसल प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। इसका सख्ती से पालन करके किसान भी भरपूर फसल उत्पादन से खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। इसलिए, किसानों के लिए यह आवश्यक है कि वे कृषि विभाग की सलाह के अनुसार अपनी फसलों की देखभाल करें।

संकलन एवं संपादन
रितेश एम.डी. भुयार
सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय, नागपुर

डाईट में केले को करें शामिल, यूरिक एसिड का लेवल रहेगा कंट्रोल में, जानें कब और कैसे करें सेवन

यूरिक एसिड बढ़ने से लोगों को हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी कई समस्याएँ होने लगती हैं। हाई यूरिक एसिड के मरीजों को अक्सर जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में सूजन और जलन जैसी कई गंभीर समस्याओं से गुजरना पड़ता है। अगर इसे सही समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके कारण गठिया और गठिया की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करना चाहते हैं तो दवाइयों के अलावा अपनी डाईट में केले को शामिल करें। केले में कई ऐसे गुण होते हैं जो यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि केला यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में कैसे काम करता है और साथ ही इसका सेवन कब और कैसे करना चाहिए।

यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में फायदेमंद है केला

केले में भरपूर मात्रा में पोटैशियम होता है जो यूरिक एसिड को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन और प्यूरीन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण यह यूरिक एसिड के मरीजों के लिए फायदेमंद है। इस फल में विटामिन सी भी होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो रक्त में यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है।

केले का सेवन कैसे करें

यूरिक एसिड के मरीज रोजाना 3 से 4 केले का सेवन कर सकते हैं। आप इसे दूध में मिलाकर भी खा सकते हैं। आप इसका शेक भी बना सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के

अनुसार इसकी खपत बढ़ा सकते हैं। आप इसे दोपहर के आसपास भी खा सकते हैं, ध्यान रखें कि सुबह खाली पेट और रात के समय इसका सेवन न करें।

न खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है, जिससे कब्ज और सूजन जैसी पेट की कई समस्याएँ नहीं होती हैं। केले में आयरन और फोलेट प्रचुर मात्रा में होता है, जो एनीमिया को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।

एंटीऑक्सिडेंट, विटामिन ए और कैरोटीनॉयड से भरपूर केला आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

दांतों की सबसे पीछे वाले हिस्से को जो दांत निकलते उन्हें दाढ़ कहते हैं। दाढ़ उम्र के बढ़ने के साथ निकलना शुरू होती है। काफी लंबे समय तक निकलती रहती है। किसी की दाढ़ 18 साल होने के बाद निकलना शुरू होती थी किसी की दाढ़ 25 से 26 में भी निकलती रहती है। ऐसे में बहुत ऐसे लोग भी जिनकी दाढ़ काफी लंबे समय तक परेशानी का कारण बनी रहती हैं।

दाढ़ आने पर मसूड़े कटने फटने लगते हैं। दांतों में सड़न होने लगती है तीव्र दर्द होता है सो अलग। ऐसे में आप अगर आप इस दाढ़ दर्द से परेशान हैं तो यहां जाने किस तरह से दर्द को दूर किया जा सकता है और घर की कौन सी चीज जो दांत के दर्द से राहत देने में असरदार साबित होती है।

दाढ़ का दर्द नहीं हो रहा ठीक तो ये घरेलू नुस्खे देखें एक बार आजमाकर

दाढ़ के दर्द की घरेलू उपाय

गर्म पानी से कुल्ला करना

दाढ़ का दर्द होने पर आराम देने के लिए और दर्द को कम करने के लिए नमक वाले पानी से मुंह से कुल्ला किया जा सकता है। 1 गिलास हल्का गर्म पानी लें और इसमें एक चम्मच नमक मिला लें। इस पानी को मुंह में रखकर यहां से वहां घुमाएं। फिर कुल्ला करके साफ कर लें। दांत के दर्द से राहत मिलेगी।

लौंग का तेल

दाढ़ के दर्द से राहत दिलाने में लौंग का तेल कारगर साबित हो सकता है। लौंग के तेल में यूजिनॉल होता है जो एंथेस्टिक की तरह काम करता है जो की एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है लौंग के तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं। दाढ़ का दर्द होने पर लौंग के तेल को किसी और तेल के साथ मिलाकर रूई पर डालें और इसे कुछ देर तक रखने के बाद धोकर हटा ले दर्द कम होने लगेगा।

खीर

दाढ़ में दर्द होने पर खीर का टुकड़ा भी दर्द कम करने में फायदेमंद होता है। खीरे के टुकड़े को दाढ़ के ऊपर रखें। यह दर्द को खींचने का काम करता है और इससे दाढ़ को ठंडक आराम मिलता है। चाहे तो खीरे का रस को रूई में डालकर आप दाढ़ पर रख सकते हैं।

यह पत्र मालक, मुद्रक, प्रकाशक मिलिंद दहीवले ने एम.पी.ऑफसेट सिरसपेठ चौक, उमरेड रोड, नागपुर यहां से मुद्रित कर कार्यालय - फ्लैट नंबर 204, दूसरा माला, साकेत अपार्टमेंट, फूलमती ले-आउट, आरोग्यम क्लीनिक के पास, नागपुर-440027 से प्रकाशित किया. मिलिंद दहीवले, मो.9552011005. email : manvadhikar2012@gmail.com वेबसाईट: www.kendriyamanvadhikar.com

This paper is printed by owner, printer and publisher Milind Dahiwalé at MP Offset, Siraspeth Chowk, Umred Road, Nagpur and published from office Flat No. 204, Second Floor, Saket Apartment, Phulmati Layout, Near Arogya Clinic, Nagpur 440027. Milind Dahiwalé Mobile No. 9552011005. email : manvadhikar2012@gmail.com वेबसाईट: www.kendriyamanvadhikar.com

केन्द्रीय मानवाधिकार समाचार पत्र में प्रकाशित सभी लेख, छायाचित्र पर संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। न्यायिक कार्यवाही केवल नागपुर न्यायालय में होगी।

न्यूज गैलरी



उच्च-मूल्य चोरी के मामलों का खुलासा, रेलवे ने जनता को दिलाया सुरक्षा का भरोसा

नागपुर – रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस की संयुक्त टीमों ने यात्रियों की संपत्ति से संबंधित दो उच्च-मूल्य चोरी के मामलों को सुलझाया है, जिससे रेलवे सुरक्षा में जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। ये मामले ट्रेन क्रमांक 11087 (वेरावल-पुणे) और ट्रेन क्रमांक 11049 (अहमदाबाद-कोल्हापुर) में यात्रा कर रहे यात्रियों से लगभग 11 तोले सोने के आभूषण (मूल्य लगभग 3,93,000/-) की चोरी से संबंधित हैं। शिकायत प्राप्त होते ही RPF और GRP की एक संयुक्त टास्क फोर्स गठित की गई। प्रारंभिक जांच में कुख्यात संसी गिरोह के सदस्यों पर संदेह हुआ। पुणे, शिवाजीनगर, लोनावला और मिर्ज रेलवे स्टेशनों से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के गहन विश्लेषण से गिरोह की संलिप्तता की पुष्टि हुई। संयुक्त टीम के समन्वित और लगातार प्रयासों से संपूर्ण चोरी गई संपत्ति बरामद कर ली गई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह सफल अभियान IG/RPF, SrDSC/पुणे और SP रेलवे पुणे के सक्षम मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। आरपीएफ ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सतर्क रहें और अपने कीमती सामान, विशेष रूप से सोने के आभूषणों, को सुरक्षित रखें। सतर्कता और सावधानी से चोरी जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सकती है।

आरपीएफ की सतर्कता से दो नाबालिगों को सुरक्षित बचाया

नागपुर – नागपुर मंडल में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने यात्रियों एवं विशेषकर बच्चों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए दो अलग-अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई कर नाबालिग बच्चों को सुरक्षित बचाया। पहले मामले में, मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष नागपुर को सूचना प्राप्त हुई कि ट्रेन संख्या 19344 पंचवटी एक्सप्रेस में एक नाबालिग बालिका अकेली यात्रा कर रही है। सूचना मिलते ही आरपीएफ पोस्ट आमला की टीम ने निर्धारित स्टेशन पर पहुंचकर बालिका को सुरक्षित उतारा और पूछताछ की। जांच में पता चला कि बालिका पारिवारिक कारणों से अकेले यात्रा कर रही थी। आवश्यक दस्तावेजी कार्यवाही पूरी करने के बाद उसे वन स्टॉप सेंटर बैतुल के सुपुर्द किया गया, जहां बाल संरक्षण अधिकारियों की उपस्थिति में उसकी देखभाल सुनिश्चित की गई। दूसरे मामले में, अजनी रेलवे यार्ड में खड़ी ट्रेन संख्या 12119 इंटरसिटी एक्सप्रेस के खाली रैक को लॉक करते समय रेलवे स्टाफ को एक नाबालिग बालक कोच में सोता हुआ मिला। उसे जगाने पर पता चला कि वह घर से भटककर गलत ट्रेन में चढ़ गया था और नागपुर पहुंच गया था। बालक अपने परिवार से संपर्क करने में असमर्थ था। आरपीएफ पोस्ट अजनी ने बच्चे को सहानुभूति एवं संवेदनशीलता से संभालते हुए उसका चिकित्सकीय परीक्षण करवाया और उसे शासकीय बालगृह नागपुर भेजा। आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे बाल न्याय मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों घटनाओं में तत्परता और मानवीय दृष्टिकोण ने यह साबित किया है कि रेलवे सुरक्षा बल केवल अपराध की रोकथाम ही नहीं करता, बल्कि असहाय एवं ज़रूरतमंद बच्चों की सुरक्षा और देखभाल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यात्रियों से अपील है कि वे किसी भी संदिग्ध स्थिति या अकेले यात्रा करते बच्चों की सूचना तुरंत आरपीएफ हेल्पलाइन 139 पर दें। यह प्रेस विज्ञप्ति मध्य रेल, नागपुर मंडल के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी की गई है।

प्रधानमंत्री ने नागपुर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई पुणे शहर रेल मार्ग के लिए प्रयास जारी – मुख्यमंत्री फडणवीस



नागपुर – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागपुर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर आठ पर आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्य अतिथि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक मोहन मते, कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके, मध्य रेलवे के महाप्रबंधक धर्मवीर मीणा, मंडल रेल प्रबंधक विनायक गर्ग और मध्य रेलवे के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागपुर (अजनी)-पुणे ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसी कार्यक्रम में उन्होंने बेंगलुरु-बेलगाम और कटरा-अमृतसर वंदे

भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। नागपुर (अजनी)-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस से नागपुर से पुणे की दूरी लगभग बारह घंटे में पूरी की जा सकेगी, जिससे यात्रा समय की काफी बचत होगी। अजनी-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस नागपुर से पुणे की यात्रा के दौरान वर्धा, बडनेरा, अकोला, धुसावल, जलगाँव, मनमाड, कोपरगाँव, अहिल्यानगर और दौंड स्टेशनों पर रुकेगी और दौंड कार्डेलाइन के माध्यम से पुणे पहुँचेगी।

इस अवसर पर रेलवे स्टेशन परिसर को मालाओं, तोरणों, झंडों और फूलों से सजाया गया था। मुख्यमंत्री और अन्य उपस्थित अधिकारियों ने यात्रियों को शुभकामनाएँ दीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, यात्री और नागरिक शामिल हुए। देश में रेलवे लाइनों

केन्द्रीय मानवाधिकार

किंडेश्वर मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं से खाई में गिरी जीप, 7 की मौत



राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता द्वारा महाराष्ट्र में जेल पुस्तकालयों के लिए बुककेस और बुकरैक उपलब्ध कराने का निर्णय

मुंबई – कैदियों के सामाजिक और शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके सुधार और पुनर्वास की दृष्टि से, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की साझा निधि योजना के अंतर्गत राज्य के 60 जेल पुस्तकालयों में से प्रत्येक को एक पुस्तक अलमारी और एक पुस्तक रैक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे ताकि कैदियों में पढ़ने के प्रति रुचि विकसित हो और उन्हें पढ़ने के अवसर मिलें, और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हो। बताया गया कि राज्य की प्रत्येक जेल में बंद कैदियों को पढ़ने का अवसर प्रदान करने, उनमें पढ़ने के प्रति रुचि विकसित करने, जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने तथा उनके सामाजिक कल्याण में सुधार लाने के लिए पुस्तकालय निदेशालय के सहयोग से बुककेस और बुकरैक उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

13 दिसंबर, 2024 को राज्य पुस्तकालय योजना समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के पुस्तकालय राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता की विभिन्न योजनाओं से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। तदनुसार, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान से अनुबंध किया गया और राज्य सरकार ने इस पर कार्रवाई की। तदनुसार, राज्य के 60 कारागार पुस्तकालयों में से प्रत्येक के लिए बुककेस और बुकरैक स्वीकृत कर दिए गए हैं और जल्द ही कारागार पुस्तकालयों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यह सामाजिक पहल पुस्तकालयों को केवल पुस्तकें रखने के स्थान के बजाय, सूचनात्मक और आकर्षक पठन केंद्रों के रूप में विकसित करने में मदद करेगी। राज्य सरकार ने अन्य पुस्तकालयों से भी अपील की है कि वे राज्य में पठन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऐसी सामाजिक योजनाओं का लाभ उठाने की पहल करें।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास प्रवेश

मुंबई – अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अवर सचिव ए. सु. जोगलेकर ने जानकारी दी है कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग, मान्य जाति, घुमंतू जाति और विशेष पिछड़ा वर्ग, ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले आधार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2025-26 के लिए छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारिणी घोषित की गई है। बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे 12वीं के बाद के पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्र और एमए, एमएससी जैसे 12वीं के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र 11 अगस्त 2025 तक छात्रावास प्रवेश के लिए आवेदन करें। आवेदनों की जांच 12 से 17 अगस्त 2025 तक की जाएगी। पहली चयन सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा और 18 अगस्त 2025 को मेरिट के आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। पहली चयन सूची में छात्रों के लिए छात्रावास प्रवेश की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 है। उसके बाद, रिक्त सीटों के लिए 2 सितंबर 2025 को मेरिट के आधार पर दूसरी प्रतीक्षा सूची प्रकाशित की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दूसरी चयन सूची में छात्रों के लिए छात्रावास प्रवेश की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2025 है।

प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी

मुंबई – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महात्मा गांधी के प्रेरक नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी वीर देशभक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने कहा कि उनके साहस ने देशभक्ति की एक चिंगारी प्रचलित की, जिसने स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत असंख्य लोगों को एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने X पर पोस्ट किया: "हम बापू के प्रेरक नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी वीर देशभक्तों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उनके साहस ने देशभक्ति की एक चिंगारी प्रचलित की, जिसने स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत असंख्य लोगों को एकजुट किया।"

पुणे – खेड़ तहसील में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी 25-30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। पुणे जिले के खेड़ तहसील में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। जीप में लगभग 15-20 लोग सवार थे, जो किंडेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे

की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने घायल लोगों को खाई से बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार, कुछ घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। यह हादसा खेड़ तहसील में उस समय हुआ, जब पापलवाड़ी गांव के लोग श्रावण मास के शुभ अवसर पर श्री क्षेत्र महादेव कुंडेश्वर मंदिर जा रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे घाट क्षेत्र

से गुजरते समय चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वैन 25 से 30 फुट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।" उन्होंने यह भी बताया कि सरकार घायलों के इलाज का खर्च उठाएगी और उन्हें हर संभव मदद प्रदान करेगी।

यूपीएससी, एमपीएससी पूर्व-प्रशिक्षण के लिए बार्टी में पंजीकरण शुरू

मुंबई –व्यापक नीति के अंतर्गत बार्टी के माध्यम से यूपीएससी, एमपीएससी पूर्व-प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण प्रारंभ हो गया है। इस प्रशिक्षण हेतु पात्र प्रशिक्षुओं का चयन सामान्य प्रवेश परीक्षा और अंक प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। बार्टी कार्यालय ने बताया है कि अंतिम चयन प्रतियोगी परीक्षा पूर्व-प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण और सीईटी अंकों के आधार पर किया जाएगा। BARTI, TRTI, SARATHI, MAHAYOJYOTI और ARTI जैसे संगठनों के माध्यम से इनके लाभार्थी समूहों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु विभिन्न परियोजनाएँ एवं योजनाएँ क्रियान्वित की जाती हैं। इन संगठनों के लाभार्थी समूहों के युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ एवं उनके पूर्व-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा एक व्यापक नीति तैयार की गई है। इस नीति के अनुसार, इन पांच संगठनों के माध्यम से राज्य के योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दिल्ली में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी पाने और उनके आर्थिक विकास में सहायता हेतु BARTI के माध्यम से एक प्रतिष्ठित निजी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यह प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। BARTI के माध्यम से इस प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

अंबरनाथ में नया न्यायालय भवन न्याय, समानता और लोकतंत्र के मूल्यों को प्रतिबिंबित करेगा- न्या. कुलकर्णी



ठाणे – बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी ने कहा कि अंबरनाथ जैसे जागरूक और गतिशील शहर में यह न्यायालय भवन न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब होगा। चिखलोली-अंबरनाथ में सिविल जज जूनियर लेवल और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालयों तथा नए न्यायालय भवन का उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी ने उपमुख्यमंत्री और ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में किया। वे इस अवसर पर बोल रहे थे।

न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अंबरनाथ जैसे स्थान पर इस न्यायालय की स्थापना से न्याय मिलने में तेजी आएगी। चिखलोली-अंबरनाथ स्थित यह न्यायालय भवन आधुनिक है और यहाँ विभिन्न आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यह आधुनिक भवन 'न्याय आपके द्वार' की अवधारणा को साकार करने में सहायक होगा। उन्होंने आगे कहा, "अंबरनाथ जैसे जागरूक और गतिशील शहर में, मुझे आशा है कि यह संरचना

न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिम्ब बनेगी। इस उद्घाटन के अवसर पर, आइए हम न्यायालय को एक जीवंत संस्था के रूप में देखें, जो केवल कानून के क्रियान्वयन के लिए ही नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास के योग्य भी है।" उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "जिस न्यायालय भवन का उद्घाटन हुआ है, वह अत्यंत सुंदर और विशाल है। अंबरनाथ के प्राचीन शिव मंदिर की तरह, यह न्यायालय भी एक पहचान बनेगा। न्याय के इस मंदिर में सत्य की सदैव विजय होगी। राज्य में निष्पक्ष न्याय की परंपरा रही है। हम अनेक उद्घाटन करते हैं, लेकिन किसी न्यायालय का उद्घाटन करना आनंद और संतुष्टि का विषय है।"

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता को न्याय दिलाने वाली सरकार है। पिछले द्वाइ साल में 32 अदालतें स्थापित की गई हैं। सरकार न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आम नागरिकों को अच्छे माहौल में न्याय मिलेगा। इसी तरह, सरकार न्याय व्यवस्था की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगी ताकि नागरिकों को न्याय मिल सके।

छोटे भाई की हत्या कर दो बार शव को दफनाया

ओडिशा – नाबालिग आरोपी ने पूछताछ में बताया कि छोटे भाई के जन्म के बाद मां-बाप का प्यार उसके लिए कम हो गया। घटना वाले दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। बोलंगीर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नाबालिग लड़के पर अपने ही छोटे भाई की हत्या का आरोप लगा है। यह मामला टिटलगाढ़ का है, जिसने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। यह पूरा मामला तब सामने आया, जब 12 साल का नारायण अचानक अपने घर से लापता हो गया। उसकी मां ने 28 जून को पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज

कराई। शिकायत के बाद नॉर्दन रेंज के आईजी के निर्देश पर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसने बोलंगीर, कालाहांडी, नुआपाड़ा और रायपुर जैसे कई जिलों में नारायण की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। कुछ समय बाद मां को अपने बड़े बेटे पर शक हुआ। उसने यह बात पुलिस को बताई। जांच के दौरान बड़े बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पुलिस के सामने चौकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी ने कबूल किया कि उसने ही अपने छोटे भाई की हत्या की है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद उसने पहले शव को घर के पीछे दफनाया था।



मार्ग बनाया जाए, तो यात्रा की दूरी कम होगी और समय की बचत होगी। भविष्य में इस संबंध में योजना बनाई जाएगी। छत्रपति संभाजीनगर, अहिल्यानगर और

पुणे औद्योगिक क्षेत्र हैं और अगर हमें यहाँ विकास करना है, तो नई रेल लाइनें बिछाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तदनुसार, छत्रपति संभाजीनगर से पुणे तक एक नया एक्सप्रेसवे

बनाया जाएगा और यदि इस रेलवे लाइन को इसके 'राइट ऑफ वे' में शामिल किया जाता है, तो यात्रा की दूरी को और कम करना संभव है।